

प्रेषक,

धीरेन्द्र सिंह दताल,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 04 जनवरी, 2017

विषय:-स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि इण्टर कालेज, हरिपुरकला (रायवाला), जनपद देहरादून का प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5ख(3)/27755/इण्टर कालेज हरिपुरकला (प्रान्तीय0) 2016-17 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि इण्टर कालेज, हरिपुरकला (रायवाला), जनपद देहरादून का प्रान्तीयकरण शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तविक रूप से अधिग्रहण की तिथि जो भी बाद में हो किये जाने एवं विद्यालय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतन बैंड (₹ में)	ग्रेड वेतन (₹ में)	सृजित पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	15600—39100	7600	01
2.	प्रवक्ता	9300—34800	4800	03
3.	सहायक अध्यापक, एल०टी०	9300—34800	4600	07
4.	वरिष्ठ सहायक	5200—20200	2800	01
5.	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	2000	02
6.	दफ्तरी	5200—20200	1800	01
7.	परिचारक	सेवायें आउटसोर्सिंग से		02 पद
योग				17 (सत्रह पद)

2. उपर्युक्त पद शिक्षा के सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे। इन पदों के पदधारकों को समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

3. राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि इण्टर कालेज, हरिपुर कला (रायवाला) जनपद देहरादून के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से सम्बन्धित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते हैं।

4. प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व-व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति इस विद्यालय को भी मुख्य शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगे। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि/भवन आदि सभी चल-अचल सम्पत्ति शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष क्लेम की बकाया रकम, कोष चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिया जायेगा। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा।
5. उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को, जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हो, इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा। इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।
6. क्रमांक 6 पर अंकित दफ्तरी के पद पर कार्यरत कार्मिक की सेवा निवृत्ति के उपरान्त दफ्तरी का 01 पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
7. ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव नहीं होगा। तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरीत क्रम से उनके द्वारा नियोक्ता अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। ये कर्मचारी अपनी नई सेवा शर्तों को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे।
8. भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त होने/उक्त के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने पर इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति कदापि नहीं की जायेगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही कार्य सम्पादन कराया जायेगा।
9. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 आय-व्ययक के अनुदान

संख्या-11 के अधीन लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-आयोजनेतर-109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय-08-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद के नामें वहन किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-86 (NP)/XXVII(3)/2016-17 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।

संख्या-1846 (1)/XXIV-4/2017-4(2)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9. वित्त विभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ/शिक्षा अनुभाग-3 एवं नवसृजित अनुभाग।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
अपर सचिव।